

EXAM GENIUS

Presents

WEEKLY GENIUS BANKING AND FINANCE

In BILINGUAL

5 - 11 APRIL 2026

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam



 UPSC

 SSC

 BANK

 RAILWAY

 STATE EXAMS

Ques: Which country will host the IMF–World Bank Annual Meetings in October 2026?

प्रश्न: अक्टूबर 2026 में IMF–विश्व बैंक की वार्षिक बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा?

- A) India / भारत
- B) Thailand / थाईलैंड
- C) USA / अमेरिका
- D) Japan / जापान
- E) Germany / जर्मनी

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Thailand will host the IMF–World Bank Annual Meetings in October 2026.
- थाईलैंड अक्टूबर 2026 में IMF–विश्व बैंक की वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा।
- The meetings will be held from 12–18 October 2026 in Bangkok.
- यह बैठक 12–18 अक्टूबर 2026 तक बैंकॉक में आयोजित होगी।
- The venue will be Queen Sirikit National Convention Center.
- इसका आयोजन क्वीन सिरिकिट नेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा।
- Thailand is hosting the meetings after a gap of 35 years.
- थाईलैंड 35 वर्षों के अंतराल के बाद इन बैठकों की मेजबानी कर रहा है।
- The country last hosted the Annual Meetings in 1991.
- इससे पहले 1991 में थाईलैंड ने इन बैठकों की मेजबानी की थी।
- Theme of the 2026 meetings is “Thailand's New Horizons: Empowering People, Building Resilience”.
- 2026 की बैठक का विषय है “Thailand's New Horizons: Empowering People, Building Resilience”।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- IMF Full Form – International Monetary Fund

- IMF का पूर्ण रूप – अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
 - World Bank – International financial institution providing loans and grants
 - विश्व बैंक – ऋण और अनुदान प्रदान करने वाला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान
 - IMF Headquarters – Washington, D.C., USA
 - IMF मुख्यालय – वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका
 - World Bank Headquarters – Washington, D.C., USA
 - विश्व बैंक मुख्यालय – वाशिंगटन डी.सी., अमेरिका
-

Ques: What is the main objective of bank account portability proposed by RBI?

प्रश्न: आरबीआई द्वारा प्रस्तावित बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) Increase bank interest rates / ब्याज दर बढ़ाना
- B) Allow multiple accounts in one bank / एक बैंक में कई खाते खोलना
- C) Switch banks without changing account number / अकाउंट नंबर बदले बिना बैंक बदलना
- D) Remove KYC requirements / KYC हटाना
- E) Stop digital payments / डिजिटल भुगतान रोकना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) is developing a bank account portability system.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) एक बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी सिस्टम विकसित कर रहा है।
- It will allow customers to switch banks without changing their account number.
- यह ग्राहकों को अपना अकाउंट नंबर बदले बिना बैंक बदलने की सुविधा देगा।
- The system is part of the Payments Vision 2028 initiative.
- यह प्रणाली Payments Vision 2028 पहल का हिस्सा है।

- It is similar to Mobile Number Portability (MNP).
- यह मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी (MNP) के समान है।
- The service is also referred to as “Payments Switching Service”.
- इस सेवा को “पेमेंट्स स्विचिंग सर्विस” भी कहा जाता है।
- It will enable seamless transfer of standing instructions like EMIs, SIPs and salary credits.
- यह EMI, SIP और सैलरी क्रेडिट जैसे स्थायी निर्देशों का आसान ट्रांसफर सुनिश्चित करेगा।
- The aim is to enhance customer convenience, competition and efficiency in banking.
- इसका उद्देश्य ग्राहक सुविधा, प्रतिस्पर्धा और बैंकिंग दक्षता को बढ़ाना है।

Ques: How many transactions were recorded by Unified Payments Interface (UPI) in March 2026?

प्रश्न: मार्च 2026 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारा कितने लेनदेन दर्ज किए गए?

- A) 22.64 billion
- B) 21.50 billion
- C) 20.39 billion
- D) 23.10 billion
- E) 24.00 billion

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Unified Payments Interface (UPI) recorded 22.64 billion transactions in March 2026.
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने मार्च 2026 में 22.64 बिलियन लेनदेन दर्ज किए।
- In February 2026, UPI transactions stood at 20.39 billion.
- फरवरी 2026 में UPI लेनदेन 20.39 बिलियन थे।

- The total transaction value in March 2026 was ₹229.53 lakh crore.
- मार्च 2026 में कुल लेनदेन मूल्य ₹229.53 लाख करोड़ रहा।
- In February 2026, the transaction value was ₹26.84 lakh crore.
- फरवरी 2026 में लेनदेन मूल्य ₹26.84 लाख करोड़ था।
- UPI is a real-time payment system that allows instant transfer of money between bank accounts using mobile phones.
- UPI एक रियल-टाइम भुगतान प्रणाली है, जो मोबाइल फोन के माध्यम से बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरण की सुविधा देती है।
- It was developed by the National Payments Corporation of India (NPCI) and launched in 2016.
- इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित किया गया और 2016 में लॉन्च किया गया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- UPI Launched – 2016
- UPI लॉन्च – 2016
- Developed By – NPCI (National Payments Corporation of India)
- विकसितकर्ता – NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया)
- Regulator – Reserve Bank of India (RBI)
- नियामक – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
- Type – Real-time Payment System
- प्रकार – रियल-टाइम भुगतान प्रणाली

Ques: The RBI's Supervisory Data Quality Index (sDQI) covers how many Scheduled Commercial Banks (SCBs)?

प्रश्न: RBI का पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक (sDQI) कितने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को कवर करता है?

- A) 72
- B) 79
- C) 83
- D) 87

E) 92

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The RBI's Supervisory Data Quality Index (sDQI) improved to 90.9 in the December 2025 quarter.
- RBI का पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक (sDQI) दिसंबर 2025 तिमाही में 90.9 हो गया।
- It was 90.7 in the July–September 2025 quarter, showing steady improvement.
- यह जुलाई–सितंबर 2025 तिमाही में 90.7 था, जो निरंतर सुधार दर्शाता है।
- The sDQI covers 87 Scheduled Commercial Banks (SCBs).
- sDQI 87 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को कवर करता है।
- The index evaluates data quality based on accuracy, timeliness, completeness and consistency.
- यह सूचकांक डेटा की सटीकता, समयबद्धता, पूर्णता और स्थिरता के आधार पर मूल्यांकन करता है।
- It includes key returns related to asset quality, risk-based supervision and liquidity.
- इसमें परिसंपत्ति गुणवत्ता, जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण और तरलता से संबंधित प्रमुख रिटर्न शामिल हैं।
- The index also assesses compliance with RBI's Master Direction on Filing of Supervisory Returns, 2024.
- यह RBI के 2024 के पर्यवेक्षी रिटर्न दाखिल करने संबंधी मास्टर डायरेक्शन के अनुपालन का भी मूल्यांकन करता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- sDQI Full Form – Supervisory Data Quality Index
- sDQI का पूर्ण रूप – पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक
- Launched by – Reserve Bank of India (RBI)
- लॉन्चकर्ता – भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
- Number of SCBs Covered – 87

- कवर SCBs की संख्या – 87

Ques: Which of the following insurers has been designated as a Domestic Systemically Important Insurer (D-SII) by IRDAI for FY 2025-26?

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस बीमाकर्ता को IRDAI द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए Domestic Systemically Important Insurer (D-SII) घोषित किया गया है?

- A) LIC / एलआईसी
- B) New India Assurance Company Ltd / न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- C) GIC Re / जीआईसी री
- D) All of the above / उपरोक्त सभी
- E) None of the above / इनमें से कोई नहीं

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has designated LIC, New India Assurance Company Ltd, and GIC Re as Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs) for FY 2025-26.
- भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने LIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और GIC Re को FY 2025-26 के लिए Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs) घोषित किया है।
- The list remains unchanged from the previous financial year.
- यह सूची पिछले वित्त वर्ष की तरह ही अपरिवर्तित रही है।
- D-SIIs are insurers whose size, market importance, and global interconnectedness make them critical to the financial system.
- D-SIIs वे बीमाकर्ता होते हैं जिनका आकार, बाजार में महत्व और वैश्विक परस्पर जुड़ाव उन्हें वित्तीय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण बनाता है।
- Their failure could lead to significant disruption in the economy.
- इनकी विफलता से अर्थव्यवस्था में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

- Separately, IRDAI has directed insurers offering digital products to self-assess compliance with guidelines on prevention of dark patterns.
- अलग से, IRDAI ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उत्पाद देने वाले बीमाकर्ताओं को 'डार्क पैटर्न' रोकने के दिशानिर्देशों के अनुपालन का स्वयं आकलन करने का निर्देश दिया है।
- These guidelines were issued by the Central Consumer Protection Authority (CCPA).
- ये दिशानिर्देश केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा जारी किए गए हैं।
- Insurers must submit compliance status within 15 days.
- बीमाकर्ताओं को 15 दिनों के भीतर अनुपालन स्थिति प्रस्तुत करनी होगी।
- Dark patterns refer to misleading UI/UX designs that manipulate users into unintended actions.
- 'डार्क पैटर्न' ऐसे भ्रामक डिज़ाइन होते हैं जो उपयोगकर्ताओं को अनजाने में गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- IRDAI Established – 1999
- IRDAI की स्थापना – 1999
- Headquarters – Hyderabad
- मुख्यालय – हैदराबाद
- Regulator – Insurance sector in India
- नियामक – भारत का बीमा क्षेत्र
- LIC – Life Insurance Corporation of India
- LIC – भारतीय जीवन बीमा निगम
- GIC Re – General Insurance Corporation of India (Reinsurer)
- GIC Re – जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (पुनर्बीमाकर्ता)
- CCPA – Central Consumer Protection Authority
- CCPA – केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

Ques: Until which date has the RBI extended the enhanced export credit period of 450 days for pre- and post-shipment finance?

प्रश्न: RBI ने पूर्व और पश्च-शिपमेंट वित्त के लिए 450 दिनों की बढ़ी हुई निर्यात ऋण अवधि को किस तारीख तक बढ़ाया है?

- A) March 31, 2026 / 31 मार्च 2026
- B) September 30, 2026 / 30 सितंबर 2026
- C) June 30, 2026 / 30 जून 2026
- D) December 31, 2026 / 31 दिसंबर 2026
- E) March 31, 2027 / 31 मार्च 2027

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has extended the enhanced export credit window of up to 450 days till June 30, 2026.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 450 दिनों तक की बढ़ी हुई निर्यात ऋण सुविधा को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है।
- This applies to both pre-shipment and post-shipment finance for all disbursements made within this period.
- यह सुविधा पूर्व-शिपमेंट और पश्च-शिपमेंट दोनों वित्त पर लागू होती है।
- The facility was originally introduced in November 2025 amid global tariff uncertainties.
- यह सुविधा मूल रूप से नवंबर 2025 में वैश्विक टैरिफ अनिश्चितताओं के बीच शुरू की गई थी।
- Earlier, it was valid for disbursements up to March 31, 2026, which has now been extended.
- पहले यह 31 मार्च 2026 तक के संवितरणों के लिए वैध थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।
- The extension was due to ongoing logistical disruptions caused by the West Asia conflict and supply chain bottlenecks.
- यह विस्तार पश्चिम एशिया संघर्ष और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं के कारण जारी लॉजिस्टिक व्यवधानों की वजह से किया गया है।
- Exporters continue to get up to 15 months (earlier 9 months) to realise and repatriate export proceeds.
- निर्यातकों को निर्यात आय प्राप्त करने और वापस लाने के लिए 15 महीने (पहले 9

महीने) की सुविधा जारी रहेगी।

Ques: What is the interest rate set by RBI for Government of India Floating Rate Bond 2028 (FRB 2028) for April–October 2026?

प्रश्न: अप्रैल-अक्टूबर 2026 के लिए RBI द्वारा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 (FRB 2028) की ब्याज दर क्या निर्धारित की गई है?

- A) 5.75%
- B) 6.00%
- C) 6.17%
- D) 6.50%
- E) 7.00%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has set the interest rate for Government of India Floating Rate Bond 2028 at 6.17% per annum.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 के लिए 6.17% प्रति वर्ष की ब्याज दर निर्धारित की है।
- This rate is applicable for the period from April 04, 2026 to October 03, 2026.
- यह दर 4 अप्रैल 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी।
- The interest rate is based on the Weighted Average Yield (WAY) of 182-day Treasury Bills plus a fixed spread of 0.64%.
- यह ब्याज दर 182-दिन के ट्रेजरी बिल के वेटेड एवरेज यील्ड (WAY) और 0.64% फिक्स्ड स्प्रेड पर आधारित है।
- The interest rate is reset every six months.
- ब्याज दर हर 6 महीने में रीसेट होती है।
- The announcement was made through an official RBI press release.
- यह घोषणा RBI की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से की गई।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Scheme – RBI Floating Rate Savings Bonds 2020 (Taxable)
- योजना – RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2020 (टैक्सेबल)
- Issued by – RBI on behalf of Government of India
- जारीकर्ता – RBI (भारत सरकार की ओर से)
- Lock-in Period – 7 years
- लॉक-इन अवधि – 7 वर्ष
- Interest Link – Linked to National Savings Certificate (NSC) + 0.35%
- ब्याज लिंक – नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) + 0.35% अतिरिक्त
- Interest Reset – Every 6 months (semi-annual payout)
- ब्याज रीसेट – हर 6 महीने (अर्धवार्षिक भुगतान)
- Minimum Investment – ₹1000 (No maximum limit)
- न्यूनतम निवेश – ₹1000 (कोई अधिकतम सीमा नहीं)
- Eligibility – NRIs not allowed
- पात्रता – NRI निवेश नहीं कर सकते
- Premature Withdrawal – Allowed only for senior citizens with penalty
- समयपूर्व निकासी – केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए दंड के साथ अनुमति
- Lock-in for Premature Withdrawal:
 - 60–70 years – 6 years
 - 70–80 years – 5 years
 - 80+ years – 4 years
- समयपूर्व निकासी हेतु लॉक-इन:
 - 60–70 वर्ष – 6 वर्ष
 - 70–80 वर्ष – 5 वर्ष
 - 80+ वर्ष – 4 वर्ष

Ques: How many states are included in the pilot launch of RBI's Benchmark Issuance Strategy (BIS) for market borrowings starting FY27?

प्रश्न: FY27 से शुरू होने वाली RBI की बेंचमार्क इश्यूंस स्ट्रैटेजी (BIS) के पायलट लॉन्च में कितने राज्यों को शामिल किया गया है?

- A) 5 States / 5 राज्य
- B) 7 States / 7 राज्य
- C) 12 States / 12 राज्य
- D) 9 States / 9 राज्य
- E) 11 States / 11 राज्य

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- RBI has decided to introduce Benchmark Issuance Strategy (BIS) for market borrowings on a pilot basis for 9 states starting FY27 (2026-27).
- RBI ने FY27 (2026-27) से 9 राज्यों के लिए पायलट आधार पर बाजार उधारी हेतु बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रैटेजी (BIS) शुरू करने का निर्णय लिया है।
- The nine states included are Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Telangana and Uttar Pradesh.
- इसमें शामिल नौ राज्य हैं — आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।
- BIS involves issuing securities in specific benchmark tenor buckets as per a pre-announced calendar to enhance transparency and provide clarity to investors.
- BIS में पूर्व-घोषित कैलेंडर के अनुसार विशिष्ट बेंचमार्क टेनर बकेट में प्रतिभूतियां जारी करना शामिल है, जिससे पारदर्शिता बढ़े और निवेशकों को स्पष्टता मिले।
- The nine BIS-adopted states are expected to collectively borrow ₹1,53,900 crore in Q1 FY27 (April–June 2026), while remaining states will borrow ₹1,00,609 crore.
- BIS अपनाने वाले नौ राज्य Q1 FY27 (अप्रैल–जून 2026) में ₹1,53,900 करोड़ उधार लेंगे, जबकि अन्य राज्य ₹1,00,609 करोड़ उधार लेंगे।
- Total market borrowings by all States/UTs for Q1 FY27 is estimated at ₹2,54,509 crore, which is lower than last year's ₹2,73,255 crore.
- Q1 FY27 के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कुल बाजार उधारी ₹2,54,509 करोड़ रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के ₹2,73,255 करोड़ से कम है।
- BIS aims to create larger and more liquid benchmark bonds under State

Development Loans (SDLs) and improve transparency in state borrowing.

- BIS का उद्देश्य राज्य विकास ऋण (SDLs) के तहत बड़े और अधिक तरल बेंचमार्क बॉन्ड बनाना तथा उधारी में पारदर्शिता बढ़ाना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Strategy Name – Benchmark Issuance Strategy (BIS)
- रणनीति नाम – बेंचमार्क इश्यूंस स्ट्रैटेजी (BIS)
- Introduced By – Reserve Bank of India (RBI)
- लागू करने वाली संस्था – भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
- RBI Role – Cash and Debt Manager of States
- RBI की भूमिका – राज्यों का नकदी और ऋण प्रबंधक
- Applicable From – FY27 (2026-27)
- लागू वर्ष – FY27 (2026-27)
- Basis – Pilot Basis
- आधार – पायलट आधार
- Number of Pilot States – 9
- पायलट राज्यों की संख्या – 9
- Pilot States – AP, Bihar, Chhattisgarh, Kerala, MP, Maharashtra, Rajasthan, Telangana, UP
- पायलट राज्य – आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश
- BIS States Q1 FY27 Borrowing – ₹1,53,900 crore
- BIS राज्यों की Q1 FY27 उधारी – ₹1,53,900 करोड़
- Non-BIS States Q1 FY27 Borrowing – ₹1,00,609 crore
- गैर-BIS राज्यों की Q1 FY27 उधारी – ₹1,00,609 करोड़
- Total Q1 FY27 Borrowing – ₹2,54,509 crore
- कुल Q1 FY27 उधारी – ₹2,54,509 करोड़
- Previous Year Q1 Borrowing – ₹2,73,255 crore
- पिछले वर्ष Q1 उधारी – ₹2,73,255 करोड़
- Instrument – State Development Loans (SDLs)
- साधन – राज्य विकास ऋण (SDLs)

Ques: Bank of Baroda's total global business crossed which milestone for the first time by March 2026?

प्रश्न: मार्च 2026 तक बैंक ऑफ बड़ौदा का कुल वैश्विक व्यवसाय पहली बार किस स्तर को पार कर गया?

- A) ₹150 lakh crore / ₹150 लाख करोड़
- B) ₹180 lakh crore / ₹180 लाख करोड़
- C) ₹200 lakh crore / ₹200 लाख करोड़
- D) ₹230 lakh crore / ₹230 लाख करोड़
- E) ₹250 lakh crore / ₹250 लाख करोड़

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Bank of Baroda crossed ₹230 lakh crore in total global business (deposits + advances) for the first time.
- बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहली बार कुल वैश्विक व्यवसाय (जमा + ऋण) में ₹230 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया।
- The total global business reached ₹230.78 lakh crore as of March end 2026.
- मार्च 2026 के अंत तक कुल वैश्विक व्यवसाय ₹230.78 लाख करोड़ हो गया।
- The bank recorded a Year-on-Year growth of 13.93% in Q4 of FY 2025-26.
- बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 13.93% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की।
- Global deposits grew by 12%, while advances increased by 16.23%.
- वैश्विक जमा में 12% और अग्रिम (लोन) में 16.23% की वृद्धि हुई।
- Deposits stood at ₹216.48 lakh crore and advances at ₹214.30 lakh crore.
- जमा ₹216.48 लाख करोड़ और अग्रिम ₹214.30 लाख करोड़ रहे।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Bank of Baroda founded : 20 July 1908

- बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना : 20 जुलाई 1908
- Headquarters – Vadodara, Gujarat
- मुख्यालय – वडोदरा, गुजरात
- MD & CEO : Debadatta Chand
- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी: देबदत्ता चंद

Ques: Razorpay has partnered with which organization to enable in-app payment integration for developers?

प्रश्न: डेवलपर्स के लिए इन-ऐप पेमेंट इंटीग्रेशन सक्षम करने हेतु रेजरपे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है?

- A) Google / गूगल
- B) Microsoft / माइक्रोसॉफ्ट
- C) OpenAI / ओपनएआई
- D) Amazon / अमेज़न
- E) IBM / आईबीएम

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Razorpay has partnered with OpenAI to enable seamless payment integration in applications.
- रेजरपे ने OpenAI के साथ साझेदारी की है ताकि ऐप्स में आसानी से पेमेंट इंटीग्रेशन किया जा सके।
- Developers can now embed payments directly into applications within minutes.
- डेवलपर्स अब कुछ ही मिनटों में सीधे ऐप्स में पेमेंट सिस्टम जोड़ सकते हैं।
- The initiative aims to simplify monetisation for AI-built products.
- इस पहल का उद्देश्य AI आधारित उत्पादों के लिए मॉनिटाइजेशन को आसान बनाना

है।

- It will help startups and developers launch paid features quickly without complex setup.
- यह स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को बिना जटिल सेटअप के जल्दी पेड फीचर्स लॉन्च करने में मदद करेगा।
- The collaboration promotes the growth of AI-driven applications and digital payments ecosystem.
- यह साझेदारी AI आधारित ऐप्स और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Razorpay Founded – 2014
- स्थापना वर्ष – 2014
- Headquarters – Bengaluru
- मुख्यालय – बेंगलुरु
- Founders – Harshil Mathur & Shashank Kumar
- संस्थापक – हर्षिल माथुर और शशांक कुमार
- OpenAI Founded – 2015
- स्थापना वर्ष – 2015
- Headquarters – San Francisco, USA
- मुख्यालय – सैन फ्रांसिस्को, USA

Ques: What is the name of the AI-powered multilingual conversational platform launched by Bank of Baroda?

प्रश्न: बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च किए गए एआई आधारित मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है?

- A) bob CONNECT / बॉब कनेक्ट
- B) bob SAMVAD / बॉब संवाद
- C) bob AI Assist / बॉब एआई असिस्ट

- D) bob ChatServe / बॉब चैटसर्व
E) bob SmartTalk / बॉब स्मार्टटॉक

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Bank of Baroda unveiled 'bob SAMVAD', an AI-powered multilingual conversational platform.
- बैंक ऑफ बड़ौदा ने 'bob SAMVAD' नामक एआई आधारित मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।
- The platform aims to transform customer interactions at bank branches.
- यह प्लेटफॉर्म बैंक शाखाओं में ग्राहक संवाद को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है।
- It is an industry-first initiative in banking for multilingual communication.
- यह बैंकिंग क्षेत्र में मल्टीलिंगुअल संवाद के लिए पहली तरह की पहल है।
- Developed entirely in-house using AI-driven speech and language technologies.
- इसे पूरी तरह से इन-हाउस एआई आधारित स्पीच और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी से विकसित किया गया है।
- It enables real-time, low-latency, two-way communication across 22 languages.
- यह 22 भाषाओं में रियल-टाइम, कम देरी वाली दो-तरफा बातचीत की सुविधा देता है।
- The platform helps eliminate language barriers between customers and bank staff.
- यह प्लेटफॉर्म ग्राहकों और बैंक कर्मचारियों के बीच भाषाई बाधाओं को दूर करने में मदद करता है।
- It promotes inclusive and customer-friendly banking services.
- यह समावेशी और ग्राहक-अनुकूल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Bank of Baroda Founded – 20 July 1908

- स्थापना – 20 जुलाई 1908
- Headquarters – Vadodara, Gujarat
- मुख्यालय – वडोदरा, गुजरात
- MD & CEO – Debadatta Chand
- एमडी और सीईओ – देबदत्ता चंद

Ques: Why did the Reserve Bank of India (RBI) cancel the licence of The Shirpur Merchants' Co-operative Bank in 2026?

प्रश्न: 2026 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने दि शिरपुर मर्चेन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द किया?

- A) Fraudulent activities / धोखाधड़ी गतिविधियों के कारण
- B) Merger with another bank / अन्य बैंक के साथ विलय
- C) Inadequate capital and poor earning prospects / अपर्याप्त पूंजी और कमजोर आय संभावनाएँ
- D) Regulatory restructuring / नियामक पुनर्गठन
- E) Voluntary closure / स्वैच्छिक बंद

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- RBI has cancelled the licence of The Shirpur Merchants' Co-operative Bank due to inadequate capital and lack of earning prospects.
- RBI ने अपर्याप्त पूंजी और कमजोर आय संभावनाओं के कारण दि शिरपुर मर्चेन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया।
- The bank ceased to carry on banking business from the close of business on April 6, 2026.
- बैंक ने 6 अप्रैल 2026 के कार्यदिवस के अंत से बैंकिंग कार्य बंद कर दिया।
- Upon liquidation, depositors are entitled to receive deposit insurance up to ₹5 lakh.

- परिसमापन के बाद, जमाकर्ताओं को ₹5 लाख तक की जमा बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- The insurance is provided by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC).
- यह बीमा राशि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारा प्रदान की जाती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- DICGC Insurance Limit – ₹5 lakh per depositor
- DICGC बीमा सीमा – ₹5 लाख प्रति जमाकर्ता
- DICGC Established – 1978
- DICGC स्थापना – 1978
- RBI Headquarters – Mumbai
- RBI मुख्यालय – मुंबई

Ques: KreditBee, recently seen in news, became a unicorn after raising how much funding?

प्रश्न: हाल ही में चर्चा में रहा KreditBee कितनी फंडिंग जुटाने के बाद यूनिकॉर्न बना?

- A) \$150 Million / 150 मिलियन डॉलर
- B) \$200 Million / 200 मिलियन डॉलर
- C) \$250 Million / 250 मिलियन डॉलर
- D) \$280 Million / 280 मिलियन डॉलर
- E) \$300 Million / 300 मिलियन डॉलर

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- KreditBee raised \$280 million (₹2,595 crore approx.) in its Series E funding

round.

- KreditBee ने सीरीज़ E फंडिंग राउंड में \$280 मिलियन (लगभग ₹2,595 करोड़)

जुटाए।

- The company is now valued at \$1.5 billion, entering the unicorn club.
- कंपनी का वैल्यूएशन अब \$1.5 बिलियन हो गया है, जिससे यह यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गई है।
- It became the second unicorn startup of 2026 after Juspay.
- यह 2026 की दूसरी यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनी है, Juspay के बाद।
- The funding round was co-led by Hornbill Capital and Motilal Oswal, with participation from Advent International, Premji Invest, and MUFUG.
- इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व Hornbill Capital और Motilal Oswal ने किया, जिसमें Advent International, Premji Invest और MUFUG ने भाग लिया।
- CEO Madhusudan Ekambaram stated that the funds will strengthen the lending book and balance sheet.
- CEO मधुसूदन एकाम्बरम के अनुसार, यह फंड लेंडिंग बुक और बैलेंस शीट को मजबूत करेगा।
- The company is preparing for an IPO by early 2027.
- कंपनी 2027 की शुरुआत तक IPO लाने की तैयारी कर रही है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Company – KreditBee
- कंपनी – KreditBee
- Sector – Fintech / Digital Lending
- क्षेत्र – फिनटेक / डिजिटल लेंडिंग
- Headquarters – Bengaluru
- मुख्यालय – बेंगलुरु
- CEO – Madhusudan Ekambaram
- सीईओ – मधुसूदन एकाम्बरम

Ques: Which group has received R1 approval from the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) to set up a new general insurance company?

प्रश्न: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) से नई जनरल इंश्योरेंस कंपनी स्थापित करने के लिए R1 स्वीकृति किस समूह को मिली है?

- A) Tata Group / टाटा समूह
- B) Aditya Birla Group / आदित्य बिड़ला समूह
- C) Mahindra Group / महिंद्रा समूह
- D) Reliance Group / रिलायंस समूह
- E) M Pallonji Group / एम पल्लोनजी समूह

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has granted R1 approval to the M Pallonji Group.
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एम पल्लोनजी समूह को R1 स्वीकृति प्रदान की है।
- The approval is for setting up a new general insurance company.
- यह स्वीकृति नई जनरल इंश्योरेंस कंपनी स्थापित करने के लिए दी गई है।
- The venture will be launched in partnership with Divya Sehgal and Federal Bank.
- यह उद्यम दिव्या सहगल और फेडरल बैंक के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा।
- As per the proposed structure, the M Pallonji Group will hold a 51% majority stake.
- प्रस्तावित संरचना के अनुसार, एम पल्लोनजी समूह के पास 51% बहुमत हिस्सेदारी होगी।
- IRDAI approval process includes three stages: R1 (business plan check), R2 (capital readiness), and R3 (final licence to start business).
- IRDAI की स्वीकृति प्रक्रिया में तीन चरण होते हैं: R1 (बिजनेस प्लान की जांच), R2 (पूंजी तैयारी), और R3 (व्यवसाय शुरू करने के लिए अंतिम लाइसेंस)।
- Kiwi General Insurance, backed by WestBridge Capital and led by former Tata AIG CEO Nilesh Garg, recently received its licence.
- वेस्टब्रिज कैपिटल द्वारा समर्थित और पूर्व टाटा AIG सीईओ निलेश गर्ग के नेतृत्व

वाली Kiwi General Insurance को हाल ही में लाइसेंस मिला है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- IRDAI Headquarters – Hyderabad
- IRDAI मुख्यालय – हैदराबाद
- Established – 1999
- स्थापना – 1999
- Chairman of IRDAI – Ajay Seth
- IRDAI के अध्यक्ष – अजय सेठ
- Federal Bank Headquarters – Aluva, Kerala
- फेडरल बैंक मुख्यालय – अलुवा, केरल

Ques: SEBI extended the validity of IPO observation letters up to which date under its one-time relaxation?

प्रश्न: SEBI ने एकबारगी राहत के तहत IPO ऑब्जर्वेशन लेटर की वैधता किस तारीख तक बढ़ाई है?

- A) June 30, 2026 / 30 जून 2026
- B) July 31, 2026 / 31 जुलाई 2026
- C) August 31, 2026 / 31 अगस्त 2026
- D) September 30, 2026 / 30 सितंबर 2026
- E) December 31, 2026 / 31 दिसंबर 2026

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) announced one-time relaxations for IPO timelines and minimum public shareholding norms.
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने IPO समयसीमा और न्यूनतम

सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग नियमों में एकबारगी राहत दी है।

- SEBI has extended the validity of observation letters expiring till September 30, 2026.
- SEBI ने 30 सितंबर 2026 तक समाप्त होने वाले ऑब्जर्वेशन लेटर्स की वैधता बढ़ा दी है।
- This move provides relief to more than two dozen companies planning to launch IPOs.
- यह कदम IPO लाने की योजना बना रही दो दर्जन से अधिक कंपनियों को राहत देता है।
- Under existing rules, observation letters are valid for 12 months, after which firms must refile draft documents.
- वर्तमान नियमों के अनुसार, ऑब्जर्वेशन लेटर की वैधता 12 महीने होती है, जिसके बाद कंपनियों को दस्तावेज़ दोबारा दाखिल करने होते हैं।
- For confidential filings, companies are given an extended window of 18 months to launch IPOs.
- गोपनीय फाइलिंग (Confidential filing) के मामलों में कंपनियों को IPO लॉन्च करने के लिए 18 महीने का समय मिलता है।
- The move aims to support companies amid market conditions and ease fundraising process.
- इस कदम का उद्देश्य बाजार परिस्थितियों में कंपनियों को सहायता देना और फंड जुटाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- SEBI Established – 1988 (Statutory status in 1992)
- स्थापना – 1988 (1992 में वैधानिक दर्जा)
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- Chairperson – Tuhin Kanta Pandey
- अध्यक्ष – तुहिन कान्त पांडेय

Ques: What is the repo rate decided by RBI's MPC in its April 2026 monetary policy meeting?

प्रश्न: RBI की MPC ने अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट कितना निर्धारित किया?

- A) 5.00%
- B) 5.10%
- C) 5.50%
- D) 5.75%
- E) 5.25%

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee (MPC) unanimously decided to keep the benchmark repo rate unchanged at 5.25%.
- भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा।
- The decision was announced on April 8, 2026.
- यह निर्णय 8 अप्रैल 2026 को घोषित किया गया।
- The MPC kept its policy stance unchanged at 'Neutral'.
- MPC ने अपना नीतिगत रुख 'न्यूट्रल' पर अपरिवर्तित रखा।
- The Standing Deposit Facility (SDF) rate remains unchanged at 5.00%.
- स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) दर 5.00% पर अपरिवर्तित रही।
- The Marginal Standing Facility (MSF) rate and Bank Rate remain unchanged at 5.50%.
- मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) दर और बैंक रेट 5.50% पर अपरिवर्तित रहे।
- Real GDP growth for FY 2026-27 is projected at 6.9% — Q1: 6.8%, Q2: 6.7%, Q3: 7.0%, Q4: 7.2%.
- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 6.9% अनुमानित — Q1: 6.8%, Q2: 6.7%, Q3: 7.0%, Q4: 7.2%।
- CPI inflation for FY 2026-27 is projected at 4.6% — Q1: 4.0%, Q2: 4.4%, Q3: 5.2%, Q4: 4.7%.
- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए CPI मुद्रास्फीति 4.6% अनुमानित — Q1: 4.0%, Q2: 4.4%,

Q3: 5.2%, Q4: 4.7% |

- The announcement was made by RBI Governor Sanjay Malhotra.
- यह घोषणा RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा की गई।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Repo Rate – 5.25%
- रेपो रेट – 5.25%
- SDF Rate – 5.00%
- SDF दर – 5.00%
- MSF Rate & Bank Rate – 5.50%
- MSF दर एवं बैंक रेट – 5.50%
- Policy Stance – Neutral
- नीतिगत रुख – न्यूट्रल
- GDP Growth (FY 2026-27) – 6.9%
- GDP वृद्धि (FY 2026-27) – 6.9%
- CPI Inflation (FY 2026-27) – 4.6%
- CPI मुद्रास्फीति (FY 2026-27) – 4.6%

Ques: What new structure has been proposed by the Reserve Bank of India (RBI) in its draft guidelines for Business Correspondents (BCs)?

प्रश्न: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स (BCs) के लिए अपने ड्राफ्ट दिशानिर्देशों में कौन-सी नई संरचना प्रस्तावित की है?

- A) Three-tier structure / तीन-स्तरीय संरचना
- B) Two-tier structure (BC-BO & BC-BT) / दो-स्तरीय संरचना (BC-BO और BC-BT)
- C) Single-tier structure / एकल संरचना
- D) Digital-only BC model / केवल डिजिटल BC मॉडल
- E) Cooperative BC structure / सहकारी BC संरचना

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has released draft guidelines proposing a major overhaul of the Business Correspondents (BCs) framework.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट्स (BCs) ढांचे में बड़े बदलाव के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- RBI has proposed a two-tier delivery structure: Business Correspondent-Banking Outlets (BC-BO) and Business Correspondent-Banking Touchpoints (BC-BT).
- RBI ने दो-स्तरीय संरचना प्रस्तावित की है: बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट-बैंकिंग आउटलेट (BC-BO) और बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट-बैंकिंग टचपॉइंट (BC-BT)।
- BC-Banking Outlets (BC-BO) are fixed service units required to operate at least 4 hours a day, 5 days a week.
- BC-BO स्थायी सेवा इकाइयाँ होंगी, जिन्हें प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे और सप्ताह में 5 दिन संचालित करना होगा।
- BC-BOs can provide services like opening accounts, deposits/withdrawals, and issuing/blocking debit cards.
- BC-BO खाते खोलने, जमा/निकासी और डेबिट कार्ड जारी/ब्लॉक करने जैसी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
- BC-Banking Touchpoints (BC-BT) will not have fixed working hours and will handle only smaller transactions.
- BC-BT के लिए निश्चित कार्य समय नहीं होगा और वे छोटे लेन-देन तक सीमित रहेंगे।
- Both BC-BO and BC-BT will work exclusively for a single bank.
- BC-BO और BC-BT दोनों केवल एक ही बैंक के लिए कार्य करेंगे।
- For remuneration, BC-BO operators will receive both fixed and variable pay.
- भुगतान के लिए BC-BO ऑपरेटरों को निश्चित और परिवर्तनीय दोनों प्रकार का वेतन मिलेगा।
- BC-BT operators will receive only variable remuneration.
- BC-BT ऑपरेटरों को केवल परिवर्तनीय वेतन मिलेगा।
- The Indian Banks' Association will decide the fixed monthly pay for eligible BC-BO agents.
- भारतीय बैंक संघ (IBA) योग्य BC-BO एजेंटों के लिए मासिक निश्चित वेतन तय करेगा।

- RBI has proposed discontinuing the Business Facilitator (BF) category, with existing entities required to transition to the BC framework by September 30, 2026.
- RBI ने बिजनेस फैसिलिटेटर (BF) श्रेणी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है और मौजूदा संस्थाओं को 30 सितंबर 2026 तक BC ढांचे में स्थानांतरित होना होगा।
- The new framework will come into effect from July 1 after finalisation, and RBI has invited comments till May 5.
- नया ढांचा अंतिम रूप के बाद 1 जुलाई से लागू होगा और RBI ने 5 मई तक सुझाव आमंत्रित किए हैं।

Ques: What is the revised GDP growth forecast for India for FY27 by the World Bank?

प्रश्न: वर्ल्ड बैंक के अनुसार FY27 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि दर क्या है?

- A) 6.0%
- B) 6.3%
- C) 6.6%
- D) 7.0%
- E) 7.5%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- World Bank has raised India's growth forecast for FY27 to 6.6%, up by 30 basis points (bps).
- वर्ल्ड बैंक ने FY27 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.6% कर दिया, जो 30 बेसिस पॉइंट (bps) की वृद्धि है।
- Growth is supported by free trade agreements and strong domestic demand.
- विकास को मुक्त व्यापार समझौतों और मजबूत घरेलू मांग से समर्थन मिला है।
- India's growth is estimated to rise from 7.1% in FY25 to 7.6% in FY26.
- भारत की विकास दर FY25 में 7.1% से बढ़कर FY26 में 7.6% होने का अनुमान है।
- Private consumption remains strong, aided by low inflation and GST

rationalisation.

- निजी उपभोग मजबूत बना हुआ है, जिसे कम मुद्रास्फीति और GST के युक्तिकरण से समर्थन मिला है।
- Growth may moderate to 6.6% in FY27 due to global headwinds like West Asia/Middle East tensions.
- पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व तनाव जैसे वैश्विक कारकों के कारण FY27 में विकास दर 6.6% तक धीमी हो सकती है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Organization – World Bank
- संगठन – वर्ल्ड बैंक
- Established – 1944
- स्थापना – 1944
- Headquarters – Washington, D.C., USA
- मुख्यालय – वॉशिंगटन डी.सी., USA
- President – Ajay Banga
- अध्यक्ष – अजय बंगा

Ques: PhonePe has launched a co-branded credit card in partnership with which bank?

प्रश्न: फोनपे ने किस बैंक के साथ मिलकर को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है?

- A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- D) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- E) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Digital payments platform PhonePe has launched a co-branded credit card in partnership with the State Bank of India.
- डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोनपे ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
- The PhonePe SBI Card is being offered with zero joining fee for the first year as a limited-period offer.
- फोनपे SBI कार्ड सीमित अवधि के ऑफर के तहत पहले वर्ष के लिए शून्य जॉइनिंग शुल्क के साथ उपलब्ध है।
- The card is available on both RuPay and Visa platforms.
- यह कार्ड RuPay और Visa दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।
- The initiative aims to expand digital payment adoption and provide more benefits to users.
- इस पहल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और उपयोगकर्ताओं को अधिक लाभ प्रदान करना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- PhonePe Founded – 2015
- फोनपे की स्थापना – 2015
- Headquarters – Bengaluru
- मुख्यालय – बेंगलुरु
- SBI Established – 1955
- SBI स्थापना – 1955
- SBI Chairman – Challa Sreenivasulu Setty
- SBI अध्यक्ष – चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी

Ques: How much total borrowing is planned by states and Union Territories in Q1 FY27 as per RBI's indicative borrowing calendar?

प्रश्न: RBI के संकेतात्मक उधारी कैलेंडर के अनुसार FY27 की पहली तिमाही में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कुल कितनी उधारी करेंगे?

- A) ₹1,53,900 crore / ₹1,53,900 करोड़
- B) ₹1,00,609 crore / ₹1,00,609 करोड़
- C) ₹2,54,509 crore / ₹2,54,509 करोड़
- D) ₹3,00,000 crore / ₹3,00,000 करोड़
- E) ₹2,00,000 crore / ₹2,00,000 करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) released the indicative borrowing calendar for Q1 FY27 (April–June 2026).
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने FY27 की पहली तिमाही (अप्रैल–जून 2026) के लिए संकेतात्मक उधारी कैलेंडर जारी किया।
- States and Union Territories are expected to collectively raise ₹2,54,509 crore.
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर कुल ₹2,54,509 करोड़ जुटाएंगे।
- RBI introduced the Benchmark Issuance Strategy (BIS) on a pilot basis to enhance transparency and provide clarity to investors.
- RBI ने पारदर्शिता बढ़ाने और निवेशकों को स्पष्टता देने के लिए पायलट आधार पर बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रेटेजी (BIS) शुरू की।
- Nine states are part of the BIS pilot: Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Telangana, and Uttar Pradesh.
- BIS पायलट में 9 राज्य शामिल हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।
- These nine states are expected to borrow ₹1,53,900 crore under BIS.
- ये 9 राज्य BIS के तहत ₹1,53,900 करोड़ उधार लेंगे।
- The remaining states and UTs will raise ₹1,00,609 crore through traditional borrowing methods.
- बाकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक तरीकों से ₹1,00,609 करोड़ जुटाएंगे।